


उक्त वाद जो विभाजित हेतु रखा गया था कि  
 प्रमाण के कारण बिकॉर्ड में परिष्करण  
 नहीं किया जा सकता है। उक्त बिकॉर्ड १९९८  
 वाद पत्र की कार्यवाही मातृगीप अधिनियम  
 जिला एवं सेशन न्यायालय इंडिया में  
 विचारधीन वाद के विषय एक उक्त वाद  
 को स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं  
 होता है। इसलिए उक्त वाद की कार्यवाही  
 को इसी स्तर पर खिंचे न्यायालय को  
 प्रमाण होने के कारण कि कौन कौन कार्यवाही  
 नहीं की जा सकती है। वाद पत्र के मातृगीप  
 अधिनियम एवं सेशन न्यायालय इंडिया में  
 विचारधीन वाद पत्र के पश्चात पुनः वाद  
 दायर करके कार्यवाही कर ली व राज्य  
 रैफरेंस के निश्चि सुचारु किया  
 जाता है। उक्त उक्त उक्त न्यायालय  
 में लिखा जाता हुआ १/१०

  
 12/12/19

